उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)
अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–63 / 2023–24

सरकार

–बनाम–

कौशिला देवी

<u>आ दे श</u>

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –2087 / अप0शा0 दिनांक –31.07.2023 के द्वारा वादी रामनाथ राय पे0–भवसागर राय सा0–नारायणपुर, थाना–तरैया जिला–छपरा (बिहार) जिला खनन पदाधिकारी गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर सिसई थाना काण्ड सं0–63 / 2023 दिनांक–21.06.2023 धारा–379 / 411 / 34 भा0द0वि0 21 खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–1957, 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004, 13 झारखण्ड खनिज(अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम–2017 के तहत् अवैध रुप से बालू का उत्खनन कर हाईवा में लोड़ कर परिवहन करते समय पकड़े जाने के आरोप में जप्त हाईवा रजि0 सं0 –JH01CU-1227 के मालिक कौशिला देवी पे0–परसु राम लोहरा सा0–तेतरटोली थाना–बेड़ो जिला–रॉंची के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि जिला खनन पदाधिकारी के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त जप्त हाईवा रजि0 सं0 –JH01CU-1227 के मालिक कौशिला देवी पे0–परसु राम लोहरा सा0–तेतरटोली थाना–बेड़ो जिला–रॉंची के विरुद्ध अवैध रुप से बालू का उत्खनन कर हाईवा में लोड़ कर परिवहन करते समय पकड़े जान के आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 (यथा) संशोधित) के नियम–4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा–4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम–7 एवं 13 के तहत् मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी के अनुपस्थित रहने के कारण उनके पक्ष को नही सुना गया। पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि हाईवा रजि0 सं0 –JH01CU-1227 के विरुद्ध अवैध रुप से बालू उठाव, परिवहन एवं चालान का दुरुपयोग करने के आरोप को सत्य पाया गया है।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:–

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being

registered as a dealer."

(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं0–360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि "Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence,the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana"

अंकनीय है कि इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन में पंजीकरण संख्या नही रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नही होने के कारण उसको अवैध रुप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त बालू एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त बालू एवं हाईवा रजि0 सं0 –JH01CU-1227 को राजसात करता हूँ।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2023.10.13 11:43:24 +05:30
Location: 192.168.5.120